



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-06072022-237111
CG-UP-E-06072022-237111

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 478]
No. 478]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 5, 2022/ आषाढ़ 14, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 5, 2022/ASHADHA 14, 1944

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2022

सा.का .नि. 512(अ).—जबकि केंद्र सरकार ने समुद्री नौचालन सहायता अधिनियम, 2021 (2021 का 20) की धारा 46 की उप-धारा (1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समुद्री नौचालन सहायता (धरोहर दीपस्तंभ) नियम, 2022 का प्रारूप, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग -II, उप खंड-(i) में, संख्या जी एस आर 99 (ई), दिनांक 02 फरवरी, 2022 के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है; और सूचना प्रदान की गई थी कि उक्त प्रारूप नियमों पर केंद्र सरकार द्वारा इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां सामान्य जन को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा;

और जबकि उल्लिखित राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां सामान्य जन को 07 फरवरी, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और जबकि, उल्लिखित प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से कोई आपत्ति और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

अतः, अब, केंद्र सरकार समुद्री नौचालन सहायता अधिनियम, 2021 (2021 का 20) की धारा 46 की उप-धारा (2) के अनुच्छेद (जे) सहित पठित धारा 23 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः—

1. **लघु शीर्षक, विस्तार-क्षेत्र एवं प्रारंभ.**— (1) इन नियमों को समुद्री नौचालन सहायता (धरोहर दीपस्तंभ का विकास) नियम, 2022 के नाम से जाना जाएगा।
 - (2) यह नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तिथि से प्रभावी होंगे।
2. **परिभाषा.**— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
 - (क) “अधिनियम” का तात्पर्य समुद्री नौचालन सहायता अधिनियम, 2021(2021 का 20) से है;
 - (ख) “कलाकृतियाँ” का तात्पर्य कला कृतियाँ मानव निर्मित वस्तुएँ जैसे उपकरण से हैं जिनके द्वारा स्वाभाविक रूप से किसी दीपस्तंभ का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक अथवा धरोहर मूल्य प्रदर्शित किया जाता है;
 - (ग) “विभाग द्वारा विकसित धरोहर दीपस्तंभ” का तात्पर्य उन विरासत दीपस्तंभों से है जिनका विकास महानिदेशक द्वारा उनको आवंटित बजट के माध्यम से किया गया है;
 - (घ) “दीपस्तंभ” में दीपपोत, धुंध संकेतक, बोया, बीकन अथवा पोत का पथ प्रदर्शित किए जाने हेतु प्रयुक्त होने वाले चिन्ह, संकेत अथवा उपकरण अभिहित हैं;
 - (ङ) “दीपस्तंभ परिसर” का तात्पर्य दीपस्तंभ स्थापित किए जाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहित, को आवंटित, पट्टे पर, किराए पर अथवा बाँटी गई भूमिका क्षेत्र है;
 - (च) “पर्यटन क्षमता” का तात्पर्य वर्तमान क्षमता अथवा संभावित क्षमता वाला क्षेत्र है जिसे पर्यटन को सुविधा जनक बनाने और आगे बढ़ाने के लिए विकसित किया जा सकता है;
 - (2) इन नियमों में प्रयुक्त लेकिन परिभाषित नहीं किए गए शब्द और अभिव्यक्ति जिनको अधिनियम में परिभाषित किया गया है, के अर्थ क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें उस अधिनियम में दिए गए हैं।
3. **धरोहर दीपस्तंभों का वर्गीकरण.**— (1) केंद्र सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत दीपस्तंभों को अपनी अंतर्निहित शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन क्षमता के दोहन हेतु निम्नलिखित मापदंडों में से किसी के आधार पर अथवा 75 वर्ष पुराने होने की दशा में धरोहर दीपस्तंभों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, नामतरः—
 - (क) समुद्री महत्व- नौचालन मार्गों का ऐतिहासिक महत्व और इन मार्गों पर तत्कालीन प्रचलित व्यापार;
 - (ख) संबद्ध इतिहास- नौचालन सुरक्षा के कारक जिन के कारण दीपस्तंभ विशेष की स्थापना की गई थी, जैसे दुर्घटनाएँ, जहाज का मलबा, भ्राम कमार्ग एवं इस प्रकार के अन्य कारण;
 - (ग) स्थान- स्थल आकृति, परिवेश, दर्शनीय पृष्ठभूमि, धार्मिक अथवा सांस्कृतिक पद चिह्न, वनस्पति एवं जीव;
 - (घ) स्थापत्य मूल्य – संरचना की विशिष्टता, इसकी वास्तुकला एवं इसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री; और
 - (ङ) पर्यटन क्षमता – पर्यटन विकास हेतु राज्य अथवा केंद्रीय एजेंसियों द्वारा निर्धारित आस-पास के स्थलों पर स्थित दीपस्तंभ।
4. **धरोहर दीपस्तंभों का विकास.**— (1) केंद्र सरकार द्वारा धरोहर दीपस्तंभों का विकास नौचालन सहायता महानिदेशालय के माध्यम से इस प्रकार किया जाएगा कि निम्नलिखित हेतु कोई व्यवधान न हो:—
 - (क) नौचालन सहायता की परिचालन स्थिति;
 - (ख) धरोहर दीपस्तंभ विशेष की संरचना एवं वास्तुकला
- (2) अन्य बातों के साथ-साथ पर्यटन क्षमता, विकास कार्यों की लागत और आवर्ती व्यय के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक के माध्यम से धरोहर दीपस्तंभों के विकास का तरीका महानिदेशक द्वारा निर्धारित किया जाएगा:—
 - (क) विभागीय रूप से विकसित हेरिटेज लाइटहाउस, अथवा
 - (ख) सार्वजनिक निजी भागीदारी जिसे केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

(3) नौचालन सहायता कार्य के अतिरिक्त धरोहर दीपस्तंभों का विकास निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु किया जाएगा:—

- (क) ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धरोहर मूल्यों का संरक्षित किया जाना; अथवा
- (ख) राष्ट्रीय समुद्री इतिहास प्रदर्शित किया जाना; अथवा
- (ग) दीपस्तंभ परिसर में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना।

(4) धरोहर दीपस्तंभों के विकास में निम्नलिखित तथ्य शामिल होंगे किंतु यह विकास केवल इन्हीं तक सीमित नहीं रहेगा:—

- (i) प्राचीन काल की प्रचलित तकनीकों एवं उसमें विद्यमान सांस्कृतिक विरासत के साथ धरोहर दीपस्तंभों एवं कलाकृतियों को नौचालन के उद्देश्य हेतु भविष्य में उनका प्रयोग किए जाने के लिए विशेष अनुरक्षण एवं मूल्य संवर्धन के माध्यम से समय-समय पर महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट तरीकों के माध्यम से उनके मूल रूप में संरक्षित और सुरक्षित किया जाएगा;
- (ii) उपरोक्त के पश्चात् भी प्राकृतिक आपदा अथवा धरोहर दीपस्तंभ के क्षय की स्थिति में जहाँ धरोहर दीपस्तंभों की संरचनात्मक अस्थिरता मानवीय जीवन और संपत्ति हेतु खतरा उत्पन्न कर सकती है, केंद्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त किए जाने के पश्चात् महानिदेशक द्वारा जैसी लागू हो, अपेक्षित वैधानिक स्वीकृति की प्राप्ति के उपरांत ऐसी संरचनाओं को हटा दिया जाएगा;
- (iii) आगंतुकों को धरोहर दीपस्तंभ की पिछली झलक दिखाने के लिए एक ऑनसाइट संग्रहालय अथवा आगंतुकों के लिए केंद्र या प्रदर्शनी क्षेत्रों जैसे बुनियादी ढांचे, जिसमें एम्फी थिएटर, म्यूजिकल फाउंटेन शामिल हो सकते हैं, महानिदेशक द्वारा विकसित किए जा सकते हैं;
- (iv) विकास इस प्रकार किया जा सकता है ताकि जनता को समुद्री समृद्धि में नौचालन सहायता के महत्व से अवगत किया जा सके और पर्यावरण संरक्षण, खोज, बचाव तथा समुद्री प्रदूषण को रोकने प्रतिक्रिया पर सार्वजनिक रूप से जनता को जागरूक किया जा सके;
- (v) आगंतुकों को धरोहर दीपस्तंभ के समीप रहने और दीपस्तंभों के संचालन में शामिल महानिदेशालय के कर्मियों के साथ शांत वातावरण, प्राकृतिक दृश्य, सांस्कृतिक परासरण एवं समुद्र के दृश्य की बदलती परिस्थितियों का अनुभव प्राप्त करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करने के लिए सीमित प्रवास (रिसॉर्ट, आगंतुक आवास) की सुविधाएँ;
- (vi) धरोहर दीपस्तंभों के परिसर का उपयोग सम्मेलनों, कार्यशालाओं, शैक्षणिक सम्मेलनों, विवाह एवं जन्म दिवस समारोह, विवाह वर्ष गाँठ आदि जैसे विशेष कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए किया जा सकता है, जिससे आगंतुकों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी; और
- (vii) सभी धरोहर दीपस्तंभों में सार्वजनिक सुविधाओं और उपयोगिताओं का प्रबंध किया जाएगा।

(5) विभागीय रूप से विकसित धरोहर दीपस्तंभों में निम्नलिखित तौर-तरीके शामिल हैं:—

- (क) धरोहर दीपस्तंभों के विकास कार्यों को विभागीय रूप से शुरू किया जाना पूँजीगत कार्य की प्रकृति में होगा और उनकी बनाई गई किसी भी संपत्ति को महानिदेशालय की अचल संपत्तियों के अंतर्गत अभिलेखित किया जाएगा;
- (ख) धरोहर दीपस्तंभों के अनुरक्षण एवं प्रबंधन हेतु जनशक्ति सहित संसाधनों को महानिदेशक द्वारा वाह्यस्रोत के आधार पर नियोजित किया जाएगा और इस पर किया जाने वाला व्यय राजस्व खाते की प्रकृति में होगा;
- (ग) आगंतुकों हेतु शुल्क संरचना का समय-समय पर निरुपित किए जाने का कार्य बड़े पैमाने पर सर्व साधारण तक पहुंच और जन जागरूकता के उद्देश्य, संचालन की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर महानिदेशक द्वारा जारी परिपत्रों के माध्यम से महानिदेशक द्वारा किया जाएगा;
- (घ) आगंतुकों के लिए शुल्क संरचना सभी धरोहर दीपस्तंभों के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित की जाएगी;

(ङ) धरोहर दीपस्तंभों के विकास, अनुरक्षण एवं प्रबंधन पर और निर्मितकोष के लिए स्रोतों पर होने वाला व्य समुद्री नौचालन सहायता अधिनियम(लेखा एवं वित्तीय शक्ति) नियम, 2022 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगा;

(च) धरोहर दीपस्तंभों के विकास और नौचालन सहायता के संचालन हेतु स्थापित संपत्तियों का अभिलेखन महानिदेशक द्वारा पृथक रूप से किया जाएगा।

(6) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से धरोहर दीपस्तंभों के विकास के तौर-तरीकों में निम्नलिखित तथ्य शामिल हो सकते हैं:—

(क) सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के माध्यम से विकसित किए जाने वाले धरोहर दीपस्तंभों के संबंध में नियम 4 के उप नियम 4 के संदर्भ में व्यवहार्य परियोजना घटक महानिदेशक द्वारा निरुपित किया जाएगा;

(ख) सार्वजनिक-निजी भागीदारी के संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार/और स्थानीय सांविधिक निकायों द्वारा जारी सभी प्रचलित दिशा-निर्देशों का पालन महानिदेशक द्वारा किया जाएगा;

(ग) केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोनी अथवा ऐसे अन्य अनुमेय उपायों के माध्यम से विकासकर्ता का चयन महानिदेशक द्वारा किया जाएगा;

(घ) सार्वजनिक निजी भागी दारी मोड पर धरोहर दीपस्तंभों के विकास को क्रियान्वित करने के लिए निर्दिष्ट रियायत अवधि हेतु चयनित विकास कर्ता के साथ महानिदेशक द्वारा एक रियायत समझौता किया जाएगा;

(ङ) धरोहर दीपस्तंभों के विकास हेतु प्रस्तावित भूमि क्षेत्र और वर्तमान संपत्तियों को यह सुनिश्चित करते हुए निर्धारित किया जाएगा कि नौचालन सहायता के रूप में धरोहर दीपस्तंभ के बुनियादी संचालन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा;

(च) रियायत समझौते के अनुसार चयनित विकास कर्ता द्वारा निर्धारित क्षेत्र और वर्तमान परि संपत्तियों का उपयोग, विकास और प्रबंधन किया जा सकता है;

(छ) परियोजना के विभिन्न घटकों जैसे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट, वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने, परियोजना की देख-रेख के लिए परियोजना के चालू रहने के दौरान डोमेन विशेषज्ञों की नियुक्ति महानिदेशक द्वारा की जा सकती है; और

(ज) रियायतग्राही धरोहर दीपस्तंभों के विशिष्ट स्थानों पर शुल्क संरचना प्रदर्शित करेगा।

5. सर्व साधारण में धरोहर दीपस्तंभों से संबंधित जानकारी का प्रसार:— (1) महानिदेशक ऐसे सभी कदम उठा सकते हैं, जैसे टिकट, पोस्टल कवर, धरोहर दीपस्तंभों पर पुस्तिकाएँ, कैटलॉग, यादगार तस्वीरें, वृत्तचित्र, विशिष्ट स्थानों पर संकेतों का प्रदर्शन, राज्य पर्यटन विभागों के साथ जानकारी साझा करना, सोशल मीडिया नेटवर्किंग, आम जनता के लिए सूचना के प्रसार हेतु दीपस्तंभ सूचना ऐप का निर्माण, जो आगंतुकों की संभ्या बढ़ाने में मदद कर सकता है और इसके परिणाम स्वरूप समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने, जन जागरूकता बढ़ाने और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

(2) महानिदेशक राज्य पर्यटन विभागों के साथ समुद्री इतिहास, सामान्य रूप से दीपस्तंभों के इतिहास और धरोहर दीपस्तंभ विशेष के इतिहास के बारे में स्थानीय पंजीकृत गाइडों को शिक्षित करने के लिए समझौता ज्ञापन या समझौते में प्रवेश कर सकते हैं ताकि क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को तालमेल बिठाया जा सके।

(3) महानिदेशक सामान्य रूप से धरोहर दीपस्तंभों या किसी धरोहर दीपस्तंभ विशेष के समग्र पर्यटन पटल को विस्तृत करने के उद्देश्य से प्रश्नगत कार्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकते हैं।

6. धरोहर दीपस्तंभों की ब्रांडिंग:- (1) धरोहर दीपस्तंभ के विकास और प्रबंधन के लिए उसकी ब्रांडिंग और प्रचार-प्रसार के लिए पर्याप्त प्रावधान पर महानिदेशक द्वारा विचार किया जा सकता है। धरोहर दीपस्तंभ की ऐसी ब्रांडिंग

और प्रचार-प्रसार हेतु किया जाने वाला व्य समुद्री नौचालन सहायता (लेखा और वित्तीय शक्ति) नियम, 2022 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार राजस्व खाते के अंतर्गत प्रभार्य होगा।

(2) स्मारिका की दुकान दीपस्तंभ परिसर के भीतर स्थापित की जा सकती है और धरोहर दीपस्तंभ प्रतीक चिन्ह के साथ उत्कीर्णित गुणवत्ता पूर्ण प्रचार सामग्री की विस्तृत शृंखला आगंतुकों के विक्रय हेतु प्रदर्शित की जा सकती है।

7. धरोहर दीपस्तंभ के विकास, परिचालन, अनुरक्षण एवं प्रबंधन से संबंधित व्य और रसीदें समुद्री नौचालन सहायता (लेखा और वित्तीय शक्ति) नियम, 2022 के प्रावधानों के अनुसार होंगी।
8. कानूनी दस्तावेज़ जिसके माध्यम से महानिदेशक द्वारा नौचालन सहायता की स्थापना के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण की गई है, अधिनियम के अनुसार ऐसी भूमि पर धरोहर दीपस्तंभों के विकास को शामिल करने के लिए उचित रूप से संशोधित किया जाएगा।
9. महानिदेशक इन नियमों के प्रावधानों के तहत गतिविधियों, सुरक्षा और सुरक्षा के रखरखाव, परिचालन आवश्यकताओं, और कार्यों के निर्वहन को विनियमित करने के लिए उपयुक्त मानक संचालन प्रक्रियाओं (एस ओपी) को विकसित और जारी करेगा, जैसा कि आवश्यक हो सकता है।

[फा. सं. एलएच-11012/1/2022-एसएल]

लुकास एल. कामसुआन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAY

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2022

G.S.R. 512(E).—Whereas the draft Marine Aids to Navigation (Heritage Lighthouses) Rules, 2022 were published, as required under sub-section (1) of section 46 of the Marine Aids to Navigation Act, 2021 (20 of 2021), vide notification of the Government of India in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways number G.S.R. 99 (E), dated the 2nd February, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from affected persons before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification were made available to the public;

Whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on 7th February, 2022;

And whereas, no objections and suggestions were received from public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 read with clause (j) of sub-section (2) of section 46 of the Marine Aids to Navigation Act, 2021 (20 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) These rules may be called the Marine Aids to Navigation (Development of Heritage Lighthouses) Rules, 2022.
(2) It shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,
 - (a) “Act” means the Marine Aids to Navigation Act, 2021 (20 of 2021);
 - (b) “artefacts” means any manmade objects, equipment, which inherently exhibit the historical or cultural or heritage value of a lighthouse;
 - (c) “departmentally developed heritage lighthouses” means the heritage lighthouses developed by the Directorate General from the budget allocated to the Directorate General;
 - (d) “lighthouse” includes any light-vessel, fog-signal, buoy, beacon, or any mark, sign or apparatus exhibited or used for the guidance of ships;
 - (e) “lighthouse premises” means an area of land acquired, allotted, leased, rented or diverted to the Central Government for establishment of a lighthouse;
 - (f) “tourism potential” means an area with existing potential or prospective potential which may be developed for facilitating and furthering tourism.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Categorisation of Heritage Lighthouses.**—(1) Lighthouses under the control of Central Government shall be categorised as heritage lighthouses which are either more than 75 years old or on the basis following parameters for harnessing its inherent educational, cultural and tourism potential, namely—

- maritime significance – historical importance of navigational routes and prevalent trades on these routes at that time;
- associated history – factors on navigational safety that necessitated establishment of particular Lighthouse, such as accidents, wrecks, misleading approaches and the like;
- location – topography, ambience, scenic background, religious or cultural footprints, flora and fauna;
- architectural value – uniqueness of structure, its architecture and materials used in its construction; and
- tourism potential – lighthouses located at nearby sites earmarked by State or Central agencies for tourism development.

4. **Development of Heritage Lighthouses.**— (1) The Central Government shall develop the heritage lighthouses through the Director General of Aids to Navigation in a manner that no disruption is caused to the:—

- operational status of aids to navigation;
- structure and architecture of the particular heritage lighthouse.

(2) The Director General shall determine the mode of development of heritage lighthouses basis, inter-alia, tourism potential, cost of development works and recurring expenses, through either of the following:—

- departmentally developed heritage lighthouses; or
- Public Private Partnership as may be approved by the Central Government.

(3) The heritage lighthouses, in addition to their function as aids to navigation shall be developed:—

- to preserve the historical, cultural and heritage values; or
- to exhibit the maritime history of the nation; or
- to promote tourism at lighthouse premises.

(4) The development of heritage lighthouses shall include but not be limited to:—

- heritage lighthouses and its artefacts with prevalent techniques of yore and the cultural lineage therein, shall be preserved and protected in their original form, irrespective of the further utilisation for the purpose of navigation or otherwise, through special maintenance and value addition in such manner as may be specified by the Director General, from time to time;
- in the event of a natural calamity or decay of the heritage lighthouse, where the structural stability of heritage lighthouses pose danger to the human lives and properties, the Director General on approval from the Central Government shall remove such structures pursuant to obtaining requisite statutory clearances, as may be applicable;
- infrastructure like onsite museum or centre for visitors or exhibition areas which may include amphitheatre, musical fountain may be developed by the Director General, showing past glimpses of heritage lighthouses to visitors;
- the development may be done in such manner so as to apprise the public of the importance of aids to navigation in maritime prosperity and also to spread public awareness on environmental protection, search and rescue and response to maritime pollution;
- facilities for limited stay (resorts, visitor accommodation) for providing the visitor a unique opportunity to stay close to the heritage lighthouse and experience the tranquil ambience, scenic view, cultural osmosis of personnel of the Directorate General involved in operation of lighthouses, and changing conditions of the seascapes;
- premises of heritage lighthouses may be used for hosting special events like conferences, workshops, educational conclaves, wedding and birthday parties, marriage anniversaries which will help in increasing visitor's footfall; and
- public convenience and utilities shall be provided at all the heritage lighthouses.

(5) The modalities for departmentally developed heritage lighthouses may include:—

- (a) the development works of heritage lighthouses to be taken up departmentally shall be in the nature of capital work and any assets created thereof shall be recorded under fixed assets of the Directorate General;
- (b) the Director General shall outsource the resources including manpower for maintenance and management of heritage lighthouse and expenditure thereof shall be in the nature of revenue account;
- (c) the Director General shall formulate the fee structures for visitors from time to time, considering access to the general public at large and objective of public awareness, sustainability of operations, and stipulate them through circulars issued by the Director General, from time to time;
- (d) the fee structure for visitors shall be displayed at the entrance of all heritage lighthouses;
- (e) the expenditure on development, maintenance and management of heritage lighthouses and accrual against built-up corpus shall be in accordance with provisions of Marine Aids to Navigation (Accounting and Financial Power) Rules, 2022; and
- (f) the Director General shall distinguish and maintain separate records of assets established for development of heritage lighthouses and operation of aids to navigation.

(6) The modalities for development of heritage lighthouses through Public Private Partnership (PPP) mode may include:—

- (a) the Director General shall formulate feasible project components, in reference with sub-rule (4) of Rule 4, in respect of the heritage lighthouses to be taken up for development on Public Private Partnership mode;
- (b) the Director General shall adhere to all prevailing guidelines issued by the Central Government or local statutory bodies from time to time concerning Public Private Partnerships;
- (c) the Director General shall select the developer through competitive bidding or such other permissible measures as per the prevailing guidelines issued by the Central Government;
- (d) the Director General shall enter into a concession agreement with the selected developer for the specified concession period for executing the development of heritage lighthouses on Public Private Partnership mode;
- (e) land area and existing assets proposed for development of heritage lighthouses shall be earmarked ensuring that there shall not be any kind of interference with the basic operation of a heritage lighthouse as an aid to navigation;
- (f) the earmarked area and existing assets may be utilised, developed and managed by the selected developer as per the concession agreement;
- (g) the Director General may engage domain experts for various components of the project such as detailed project report, techno-economic feasibility report, obtaining statutory clearances, overseeing the project, during the currency of the project, and
- (h) the concessionaire shall display the fee structure at conspicuous locations of heritage lighthouses.

5. **Dissemination of information on heritage lighthouses to public.**—(1) The Director General may take all such steps, such as bringing out stamps, postal covers, booklets on heritage lighthouses, catalogues, memorable photographs, documentaries, display of signs at conspicuous places, sharing of information with State tourism departments, social media networking, creation of lighthouse information app for dissemination of information to general public, which may help in increasing visitors footfall and consequently promoting maritime safety, raising public awareness and shall help in boosting local business.

- (2) The Director General may enter into memorandum of understanding or agreement with the state tourism departments for educating local registered guides about the maritime history, history of lighthouses in general and history of particular heritage lighthouse to synergise tourism potential of the region.
- (3) The Director General may engage domain experts in the field for widening the overall tourism canvas of heritage lighthouses in general or a particular heritage lighthouse.

6. **Branding of heritage lighthouses.**—(1) The Director General may consider adequate provision for branding and promotion of heritage lighthouse for its development and management and the expenditure towards such branding and promotion of the heritage lighthouse shall be charged under revenue account in accordance with the provisions of the Marine Aids to Navigation (Accounting and Financial Power) Rules, 2022.

(2) Souvenir shops may be established within the Lighthouse complex and range of quality promotional materials embossed with heritage lighthouse insignia may be kept for sales to visitors.

7. The expenditure and receipts pertaining to the development, operation, maintenance and management of heritage lighthouses shall be in accordance with provisions of Marine Aids to Navigation (Accounting and Financial Power) Rules, 2022.

8. The legal documentation through which lands have been acquired by the Director General for the purpose of establishment of aids to navigation shall be amended appropriately to incorporate the inclusion of development of heritage lighthouses on such lands in accordance with the Act.

9. The Director General shall develop and issue suitable Standard Operating Procedures (SOPs), as may be required, to regulate the activities, maintenance of safety and security, operational requirements, and discharge of functions to be performed under the provisions of these Rules.

[F. No. LH-11012/1/2022-SL]

LUCAS L. KAMSUAN, Jt. Secy.